सूचना

यदी आप को नियमित दैनिक सुफ्फा का अंक प्राप्त नही हो रहा है या फिर आप दैनिक सुफ्फा हासिल करना चाहते है तो इस नम्बर पर संपर्क करे- 7620469536

औरंगज़ेब हुसैन (कार्यकारी संपादक)

epaper:suffahdailynews.com

दैनिक

सुफ्फा

आम आदमी की आवाज़..।

मुख्य संपादकः सज्जाद हुसैन अल्ताफ हुसैन

R.N.I. MAHHIN/2017/70719

Email:suffaakl@gmail.com ■ साल ८ वा ■ अंक ९१ ■ सोमवार २९ अप्रैल २०२४ ■ अकोला ■ पृष्ठ ४ ■ मूल्य ३ रूपये

जम्मू-कश्मीर: घोटालों के जांचकर्ता सीबीआई अधिकारी की सड़क हादसे में मौत, पीडीपी द्वारा जांच की मांग

नई दिल्ली-

जम्मू-कश्मीर में कई घोटालों की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक अधिकारी की सड़क दुर्घटना में कथित तौर पर मौत हो गई है. इस संबंध में अधिकारियों ने शनिवार (२७ अप्रैल) को जानकारी दी, जिसके बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने इस घटना की जांच की मांग की है.रिपोर्ट के अनुसार, मृत सीबीआई अधिकारी की पहचान पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत शर्मा के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात अधिकारी जब अपने कार्यालय से घर लौट रहे थे, तब उनकी मोटरसाइकिल जम्मू शहर के एक निजी स्कूल के बाहर बनिहाल कार्ट रोड पर संतुलन खो बैठी.ये दुर्घटना शुक्रवार रात करीब १२ बजे हुई, उस समय जम्मू शहर में कथित तौर पर बारिश हो रही थी, इसलिए अधिकारी को गंभीर चोटें आईं.खबरों के अनुसार, जम्मू के पलौरा इलाके के मांडलिक नगर निवासी शर्मा ने अपने घर के रास्ते में (शेष पृष्ठ ३ पर)

BJP पर क्यों नहीं होती कार्रवाई? AAP का कैंपेन सॉन्ग बदलने के EC के आदेश पर बोलीं आतिशी

नई दिल्ली-

लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को अपने इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग में बदलाव करने को कहा है. EC ने कहा कि सॉन्ग की लाइन 'जेल के जवाब में हम वोट देंगे' के साथ आक्रोशित भीड़ नजर आ रही है. इस भीड़ के हाथ में जेल की सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है. इस तरह के पिक्चराइजेशन से न्यायपालिका की छवि खराब होती है. EC के इस आदेश को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने BJP को निशाने पर लिया है.आम आदमी पार्टी सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तानाशाही का सबूत जनता के सामने रख दिया है. AAP नेता ने कहा, 'अगर ँव्ह तानाशाही करती है, तो यह सही है. लेकिन अगर कोई इसके बारे में बात करता है, (शेष पृष्ठ ३ पर)

हम २ प्रधानमंत्री बनाएं या ४ हमारी मर्जी, तानाशाही नहीं आने देंगे..

संजय राउत का पीएम मोदी को जवाब

नई दिल्ली-

देश में लोकसभा चुनाव पूरे शबाव पर है. ७ चरणों में होने वाले चुनाव के दो चरण संपन्न हो चुके है. सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे है. इस दौरान जमकर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं. इस बीच शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने पीएम को तानाशाह करार दिया है.पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दस सालों एक तानाशाह देश चला रहा है. पीएम मोदी के हर साल एक नया पीएम बनाए जाने के बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार लोकतांत्रिक रूप से चुने गए तानाशाह से कहीं बेहतर है. उन्होंने कहा कि देश को एक हुकुमशाह चला रहा है जिसे लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया था वो तानाशाह बन गया है.राउत ने कहा कि हम किसे अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं यह हमारी इच्छा है. ये हम लोगों की मर्जी है कि हम २ प्रधानमंत्री बनाएं या ४ प्रधानमंत्री बनाएं. उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए इस देश को तानाशाही की ओर नहीं जाने दिया जाएगा. इसके आगे संजय राउत ने कहा आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ३०० से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगा. इसके साथ ही दो चरणों के मतदान को लेकर भी संजय राउत ने बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि दो फेस के जो चुनाव हुए हैं उससे साफ जाहिर हा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार रहे हैं. दरअसल मध्य प्रदेश के बैतूल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि इंडी गठबंधन में चर्चा चल रही है कि इंडी अलायंस वाले वन ईयर वन पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी एक साल एक पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, पांचवें साल पांचवां पीएम. ये पीएम की कुर्सी का भी ऑक्शन करने में लगे हैं.आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है. महाराष्ट्र में ४८ लोकसभा सीटें है. राज्य में पांच चरणों में मतदान होने जा रहा है. वहीं चरणों का मतदान पूरा हो चुका है. बीते २६ अप्रैल को महाराष्ट्र की आठ सीटों पर मतदान हुआ था. ७ और २० मई के बीच तीन और चरणों में मतदान होगा.

सिद्दरमैया ने केंद्र के 'अन्याय' के खिलाफ दिया धरना

खाली लोटा हाथ में पकड़कर नेताओं ने किया प्रदर्शन

बैंगलुरू-

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मंत्रियों और विधायकों के साथ रविवार को धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सूखे से निपटने के लिए राहत राशि जारी करने में राज्य के साथ अन्याय किया है। खाली लोटा हाथ में पकड़े नेताओं ने केंद्र पर सूखे से निपटने के लिए पर्याप्त राहत जारी न कर कर्नाटक को धोखा देने का आरोप लगाया। बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, मंत्रियों और विधायकों के साथ रविवार को धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सूखे से निपटने के लिए राहत राशि जारी करने में राज्य के साथ अन्याय किया है। खाली लोटा हाथ में पकड़े नेताओं ने केंद्र पर सूखे से निपटने के लिए पर्याप्त राहत जारी न कर कर्नाटक को धोखा देने का आरोप लगाया।राज्य सरकार ने कर्नाटक के कुल २३६ तालुकाओं में से २२६ को सूखाग्रस्त घोषित किया है। कहा है कि ४८ लाख हेक्टेयर भूमि में फसल का नुकसान हुआ है। सिद्दरमैया अनुसार, सूखे से निपटने के लिए १८,१७१ करोड़ रुपये की मांग के बदले केंद्र सरकार ने केवल ३,४५४ करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह आदेश भी राज्य द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के बाद दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह राशि राज्य की मांग का एक चौथाई भी नहीं है।

मुंबई पुलिस ने बच्चों को बेचने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, डॉक्टर समेत ७ गिरफ्तार

नई दिल्ली-

मुंबई पुलिस ने बच्चों को बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में एक डॉक्टर समेत ७ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की तरफ से बताया गया है कि इस मामले में २ शिशुओं को गिरोह से छुड़ाया भी गया है. चौंकाने वाली बात यह है कि इस गैंग में एक डॉक्टर भी शामिल है. मुंबई पुलिस ने जानकारी दी है कि फर्टिलिटी सेंटरों में काम करने वाली महिलाओं की मदद से यह रैकेट चलाया जा रहा है. जांच में पता चला है कि गिरोह अब तक १४ बच्चों को बेच चुका है.पुलिस ने बच्चों को बेचने वाली महिला दलाल समेत कुल ७ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही गहन पूछताछ के लिए तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में वंदना अमित पवार, शीतल गणेश वारे, स्नेहा सूर्यवंशी, नसीमा खान, लता सुरवाडे, शरद देवार और डॉ. शामिल हैं. संजय सोपानराव खंडारे शामिल हैं. सभी आरोपियों को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. इस गिरोह के जरिए आरोपियों द्वारा बेचे गए(शेष पृष्ठ ३ पर)

महादेव सट्टेबाजी ऐप: गिरफ्तार एक्टर साहिल खान, ४ दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

नई दिल्ली-

बॉलीवुड एक्टर साहिल खान को मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने गिरफ्तार में ले लिया है. साहिल खान पर बेटिंग साइट चलाने और बेटिंग को प्रमोट करने का आरोप है. जिसके तहत उन पर कार्रवाई की गई है. एसआईटी ने साहिल को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से गिरफ्तार किया है. जिसके बाद उन्हें मुंबई लाया गया. जिसके बाद साहिल को शिंदेवाड़ी-दादर कोर्ट में पेश किया गया. उन्हें १ मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. मीडिया सके सवालों पर एक्टर साहिल खान ने कहा कि उन्हें मुंबई पुलिस और देश के कानून पर पूरा भरोसा है और सच्चाई सामने आएगी.जानकारी के मुताबिक मुंबई के माटुंगा पुलिस महादेव बेटिंग ऐप केस की जांच में एक्टर साहिल खान का नाम आया था. साहिल द लायन बुक एप नाम के एक सट्टेबाजी (शेष पृष्ठ ३ पर)

राजस्थान: मोदी की आलोचना पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से निष्कासित नेता अब पुलिस की हिरासत में

जयपुर-

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राजस्थान की बीकानेर पुलिस ने शनिवार (२७ अप्रैल) को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष उस्मान गनी को हिरासत में ले लिया. अधिकारियों ने बताया कि गनी पर 'शांति भंग' करने का आरोप है. गनी हाल ही में तब सुर्खियों में आए थे जब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें उन्होंने न्यूज़ २४ से बात करते हुए बांसवाड़ा की एक चुनावी रैली के दौरान दिए बयानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी. प्रधानमंत्री के भाषण पर गनी की टिप्पणियों के बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था.बीकानेर पुलिस ने कहा कि गनी को मुक्ता प्रसाद नगर पुलिस स्टेशन में 'पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार और टकराव' के बाद एहतियातन हिरासत में लिया गया है.मुक्ता प्रसाद नगर पुलिस थाने के एसएचओ धीरेंद्र शेखावत ने बताया, 'प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिए उनके बयान पर कड़ी आलोचना और प्रतिक्रिया देखी गई थी, जिसके बाद कुछ दिन पहले उनके घर के इलाके में एक पुलिस वाहन यह देखने के लिए भेजा गया था कि क्या वह ठीक और सुरक्षित हैं. यह एक (शेष पृष्ठ ३ पर)

अमेठी के लिए राहुल तैयार नहीं, प्रियंका भी कन्फ्यूजन मेंष्ठ आखिर कहां अटक रही बात

नई दिल्ली-

उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर अभी भी सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है. माना जा रहा था कि इस बार राहुल गांधी वायनाड के साथ-साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे जबकि प्रियंका गांधी को रायबरेली से उतारा जा सकता है, लेकिन अब इसके आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं. इसलिए, क्योंकि राहुल गांधी ने अमेठी से भी चुनाव लड़ने पर अपनी सहमति नहीं दी है. सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि जिस समय अमेठी में उन्हें हार मिली थी उस समय वायनाड की जनता ने उन पर भरोसा किया था और उन्हें सांसद बनाया.बताया जाता है कि शनिवार को हुई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी को अमेठी से और प्रियंका गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार घोषित करने का अनुरोध किया था. सीईसी ने अमेठी और रायबरेली की सीट पर फैसला अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर छोड़ दिया था. इसके बाद खबर आई कि मल्लिकार्जुन खरगे ने दोनों सीट पर फैसला गांधी परिवार पर छोड़ दिया है. मतलब अमेठी सीट से राहुल गांधी मैदान में उतरेंगे या नहीं यह गांधी परिवार ही तय करेगा.सूत्रों के मुताबिक, आज रात गांधी परिवार के सदस्यों की आपस में एक बैठक होने वाली है. इस बैठक में पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ-साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी. इस बैठक में राहुल की अमेठी से उम्मीदवारी को लेकर चर्चा होगी और संभव है कि कल तक इस पर फैसला(शेष पृष्ठ ३ पर)

फैक्ट-चेक: प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी भाषणों में लगातार झूठे दावे कर रहे हैं

नई दिल्ली-

पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में दिए गये चुनावी भाषणों को लेकर स्क्रॉल ने एक फैक्ट-चेक प्रकाशित किया है, जिसमें बताया गया है कि मोदी ने इन सभाओं में बार-बार झूठ बोला है. उक्त भाषण २१ अप्रैल से २५ अप्रैल की अवधि के बीच के हैं.

अप्रैल २१, बांसवाड़ा

दावा: प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है कि वह विवाहित हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र सहित निजी संपत्ति का सर्वे करेगी, जब्त करेगी और उसे (मुसलमानों में) बांट देगी. उन्होंने कहा था, 'मेरी माताओं- बहनों की जिंदगी में सोना सिर्फ दिखावा करने के लिए नहीं होता है, उनके स्वाभिमान से जुड़ा होता है. मंगलसूत्र उनके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ होता है, तुम अपने घोषणापत्र में उसे छीनने की बात कर रहे हो .'

तथ्य: कांग्रेस के घोषणापत्र में निजी संपत्ति जब्त करने का कोई जिक्र नहीं है, महिलाओं का मंगलसूत्र छीनना तो दूर की बात है.

दावा: मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस की पिछली सरकार ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है.

तथ्य: यहां मोदी ने २००९ में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा दिए गए एक भाषण के शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश किया था. मनमोहन सिंह ने तब केवल धार्मिक अल्पसंख्यक ही नहीं, बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और बच्चों सहित सभी वंचित वर्गों के उत्थान की आवश्यकता के बारे में बात की थी.

दावा: मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस आपकी संपत्ति इकट्ठा करके 'घुसपैठियों' और 'जिनके ज्यादा बच्चे हैं' उन्हें बांट देगी – यहां उनका इशारा मुसलमानों की तरफ था.

तथ्य: इस बात का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है कि मुसलमान 'घुसपैठिए' हैं – मोदी सरकार ने संसद को बार-बार बताया है कि उसके पास अवैध आप्रवासियों पर कोई डेटा नहीं है। भारतीय मुसलमानों की प्रजनन दर, हालांकि हिंदुओं से अधिक है, अन्य सभी समुदायों की तुलना में तेजी से घट रही है. इसके अलावा, प्रजनन अर्थशास्त्र का विषय है, न कि धर्म का; अधिक विकसित तमिलनाडु में मुसलमान गरीब राज्य बिहार के हिंदुओं की तुलना में कम बच्चे पैदा करते हैं.

अप्रैल २२, अलीगढ़

दावा: मोदी ने वही झूठा दावा दोहराया कि कांग्रेस के घोषणापत्र में निजी संपत्ति का सर्वेक्षण करने और उसे जब्त करने की बात कही गई है. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस के शहज़ादे (कांग्रेस नेता राहुल गांधी) का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान हैं, उसकी जांच कराएंगे. इतना ही नहीं वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है, उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर सबको बांट देगी. यह उनका घोषणापत्र कहता है.'

तथ्य: कांग्रेस के घोषणापत्र में यह नहीं कहा गया है. ६ अप्रैल को घोषणापत्र जारी करते समय राहुल गांधी ने कहा था, 'हम देश का एक्स-रे करेंगे. पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, सामान्य वर्ग के गरीब लोगों और अल्पसंख्यकों को पता चल जाएगा कि देश में उनकी हिस्सेदारी कितनी है.' हालांकि, उन्होंने यह नहीं कहा था कि पार्टी निजी संपत्तियों को जब्त करेगी और बांट देगी.

दावा: कांग्रेस यहां तक जाएगी, अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों को भविष्य के लिए आपने शहर में छोटा फ्लैट ले लिया. और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है, तो दो में से एक छीन लेंगे. आपको दो की जरूरत नहीं है. जिसको नहीं, उसको दे देंगे। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपके पास गांव में एक घर तो पहले से ही है. ये माओवादी सोच है? कांग्रेस आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर अपना पंजा मारना चाहती है. आपका स्त्री धन लूटना चाहती है.

तथ्य: कांग्रेस के घोषणापत्र में बांटने संबंधी एकमात्र संदर्भ यह है: 'कांग्रेस भूमि सीमा अधिनियम के तहत गरीबों को सरकारी भूमि और अधिशेष भूमि के वितरण की निगरानी के लिए एक प्राधिकरण स्थापित करेगी.' यह शायद ही कोई नया क्रांतिकारी वादा है, क्योंकि भारत के २१ राज्यों में पहले से ही भूमि सीमा कानून हैं, जिन्हें १९६० के दशक में (शेष पृष्ठ ३ पर)

अग्रलेख

भारतीय संविधान और हिंदुत्व के पैरोकारों की अंतहीन बेचैनी

कुछ तारीखें हर जम्हूरियत की तवारीख में सदा के लिए अंकित हो जाती हैं. ६ दिसंबर १९९२ ऐसी ही एक तारीख है. इस घटना के तीन सप्ताह के अंदर दिल्ली में एक प्रेस सम्मेलन हुआ था. २५ दिसंबर १९९२ को स्वामी मुक्तानंद और वामदेव महाराज, जो राम मंदिर आंदोलन से क़रीब से जुड़े थे, उन्होंने मौजूदा संविधान को बदलने की बात छेड़ दी और कहा कि यह संविधान 'हिंदू विरोधी है'. (इंडिया टुडे, ३१ जनवरी १९९३) एक सप्ताह बाद १ जनवरी १९९३ को स्वामी मुक्तानंद के नाम से हिंदूवादी संगठनों की तरफ से एक श्वेत पत्र जारी किया गया, जिसमें भारतीय संविधान को 'हिंदू विरोधी' घोषित किया गया था. श्वेत पत्र के कवर पेज पर दो प्रश्न पूछे गए थेः एक, 'भारत की एकता, बंधुत्व और सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट किसने किया?' और ' किसने भुखमरी, गरीबी, भ्रष्टाचार और अधर्म फैलाया ?'श्वेत पत्र का शीर्षक इस प्रश्न का जवाब दे रहा था , 'वर्तमान इंडियन संविधान'!श्वेत पत्र की प्रस्तावना स्वामी हीरानंद ने लिखी थी, जिसमें यह लिखा था कि 'भारत का संविधान यहां की संस्कृति, चरित्र, परिस्थिति आदि के विपरीत है, वह विदेशोन्मुखी है. 'इस प्नरस्तावना ने न केवल संविधान को 'खारिज करने की' बात की थी बल्कि यह भी जोर देकर कहा था कि 'दो सौ साल की ब्रिटिश हुकूमत ने जितना भारत का नुकसान किया, उससे अधिक नुकसान भारत के संविधान ने किया है. 'इस श्वेत पत्र पर सबसे पहली प्रतिक्रिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया की तरफ से आई थी. १४ जनवरी १९९३ को इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने लिखा थाः'वर्तमान विवाद की जड़ों को आंशिक तौर पर हम असली भारत की जरूरतें, उसकी परंपरा, मूल्यों को संबोधित कर पाने में हमारी व्यवस्था की कमियों में देख सकते हैं ष्ठ इस मुल्क की कुछ विशेषताओं को संविधान में प्रतिबिंबित होना चाहिए था, 'इंडिया दैट इज भारत' की जगह 'भारत दैट इज हिंदुस्तान' कहना चाहिए था. आधिकारिक दस्तावेज भारत में 'साझी संस्कृति' की बात करते हैं, मगर यहां कोई 'साझी संस्कृति नहीं' है. ष्ठसंविधान में बदलाव निहायत जरूरी हैं. एक ऐसा संविधान अपनाना चाहिए जो यहां के इथॉस (लोकाचार/संस्कार) और प्रतिभा के अनुकूल हो. 'यह न पहला मौका था, और न आखिरी जब संघ ने संविधान पर सवाल उठाए थे और भारतीय संस्कृति में रचे बसे संविधान बनाने की बात की थी. गौर करें, २०२४ के संसदीय चुनाव के दौरान कई भाजपा सदस्यों ने संविधान बदलने की बात कही है. मौजूदा संविधान को खारिज करने और भारतीय पहचान के आधार पर नया संविधान बनाने की बात करने में भाजपा का पितृसंगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा आगे रहा है. जब १९४९ नवंबर में संविधान सभा ने भारत के संविधान पर अपनी मुहर लगाई, उसके सिर्फ तीन दिन बाद 'ऑर्गनाइज़र' ने अपने संपादकीय में मनुस्मृति की हिमायत करते हुए संविधान की तीखी आलोचना कीःहमारे संविधान में प्राचीन भारत के विलक्षण संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है. मनु की विधि स्पार्टा के लाइकरगुकस या पर्शिया के सोलोन के बहुत पहले लिखी गई थी. आज तक इस विधि की, जो 'मनु स्मृति' में उल्लिखित है, विश्वभर में सराहना की जाती रही है और यह स्वतःस्फूर्त धार्मिक नियम पालन तथा समानुरूपता पैदा करती है. लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए उसका कोई अर्थ नहीं है. '(ऑर्गनाइज़र, ३० नवंबर १९४९, पेज ३)मनु की किताब को स्वाधीन भारत की सरजमीं पर लागू करने की मांग सिर्फ 'ऑर्गनाइज़र' ने नहीं उठाई थी. विनायक दामोदर सावरकर भी इस किताब को भारतीय कानून की नींव बतौर देखते थे. 'मनुस्मृति में स्त्रियां' नामक लेख में वह लिखते हैंः'मनुस्मृति वह ग्रंथ है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए वेदों के बाद सबसे अधिक व्यवहार्य है और जो प्राचीन समय से हमारी संस्कृति-रिवाजों, चिंतन और व्यवहार का आधार रहा है. हमारे राष्ट्र की आध्यात्मिक और दैवी यात्रा को उसी ने सदियों से संहिताबद्ध किया है. आज भी करोड़ों हिंदुओं द्वारा अपनी जिंदगियों में और आचरण में जिन नियमों का पालन किया जाता है वह मनुस्मृति पर आधारित है. आज मनुस्मृति ही हिंदू कानून है. 'जब डॉ. आंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से हिंदू स्त्रियों को पहली दफा संपत्ति और तलाक के मामले में अधिकार दिलाने की बात की थी, तब कांग्रेस के अंदर के रूढ़िवादी धड़े से लेकर हिंदूवादी संगठनों ने उनकी मुखालिफत की थी, उसे हिंदू संस्कृति पर हमला बताते हुए उनके घर तक जुलूस निकाले गए थे. सरसंघचालक एम एस गोलवलकर ने उन दिनों लिखा थाः 'जनता को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए तथा इस संतोष में भी नहीं रहना चाहिए कि हिंदू कोड बिल का खतरा समाप्त हो गया है. वह खतरा अभी ज्यों का त्यों बना हुआ है, जो पिछले द्वार से उनके जीवन में प्रवेश कर उनकी जीवन की शक्ति को खा जाएगा. यह खतरा उस भयानक सर्प के सदृश है, जो अपने विषैले दांत से दंश करने के लिए अंधेरे में ताक लगाए बैठा हो. इतिहास में पहली बार इस बिल के जरिये विधवा को और बेटी को बेटे के समान संपत्ति के अधिकार दिलाने, एक जालिम पति को तलाक देने का अधिकार पत्नी को दिलाने, दूसरी शादी करने से पति को रोकने, अलग-अलग जातियों के पुरुष और स्त्री को हिंदू कानून के अंतर्गत विवाह करने और एक हिंदू जोड़े के लिए दूसरी जाति में जन्मे बच्चे को गोद लेने आदि बातें प्रस्तावित की गई थीं. लेकिन हिंदुत्व के कई पैरोकार सिर्फ़ इस बिल का विरोध कर रहे थे, वे दलितों और आदिवासियों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए नवस्वाधीन मुल्क द्वारा लिए गए सकारात्मक कार्रवाई के प्रति भी अपनी असहमति दर्ज करा रहे थे कि इसके जरिये शासकवर्ग हिंदू सामाजिक एकता की जड़ों पर चोट कर रहे हैं और अतीत में जिस सद्भावपूर्ण माहौल में हिंदू धर्म के तमाम संप्रदाय एक पहचान की भावना के तहत रहते थे, उस भावना को चोट पहुंचाई जा रही है.

यह समाचार पत्र मालक, प्रकाशक **सज्जाद हुसेन अलताफ हुसेन**, इन्होने मुद्रक - औरंगज़ेब हुसेन सज्जाद हुसेन, मुद्रण स्थल- **हुसेनी प्रिंटींग प्रेस,** हुसेनी कॉम्प्लेक्स, वाशिम बायपास, अकोला ता.जि. अकोला (महाराष्ट्र) यहा छापकर ऑफीस : **दैनिक सुफ्फा,** जनता भाजी बाज़ार, अकोला जि. अकोला यहां से प्रकाशित किया. **संपादक : सज्जाद हुसेन अलताफ हुसेन** प्रकाशित लेख और खबरों से संपादक सहमत है ऐसा नही. (पी.आर.बी.ॲक्ट के अनुसार संपादक उत्तरदायी होंगे) सभी प्रकरण अकोला न्यायालय के अंतर्गत रहेंगे.

व्हाइट हाउस डिनर से फिलिस्तीन पत्रकारों ने बनाई दूरी, गाजा में कई जर्नलिस्ट्स की गई है जान

वाशिंगटन-
व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन के डिनर का आयोजन पिछली रात यानी २७ अप्रैल को किया गया. इस साल हुए इस डिनर का आयोजन काफी अलग परिस्थितियों में हुआ. हर साल होने वाले इस डिनर में पत्रकार, राजनेता और कई मशहूर हस्तियां शामिल होती हैं. लेकिन इस बार के डिनर में फिलिस्तीनी पत्रकारों ने डिनर को बॉयकॉट करने का ऐलान किया था.ॅर्ण्ं पत्रकारों का एक संगठन है जो व्हाइट हाउस और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को कवर करता है.व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन पत्रकारों का एक संगठन है जो व्हाइट हाउस और अमेरिका के राष्ट्रपति को कवर करता है. इस डिनर में वीआईपी मेहमानों की लंबी लिस्ट तैयार की गई थी, जिसमें सबसे पहला नाम राष्ट्रपति जो बाइडेन का था. इस हफ्ते की शुरुआत में काफी संख्या में फिलिस्तीन पत्रकारों ने अपने अमेरिकी सहयोगियों के लिए एक ओपन लेटर जारी किया, जिसमें आयोजित हुए डिनर को बॉयकॉट करने की अपील की गई थी. फिलिस्तीन पत्रकारों के जारी किए गए इस लेटर में कहा गया कि हम सभी के पास पत्रकारों की ईमानदारी को बनाए रखने के लिए सत्ता के

सामने सच बोलने की एक अनोखी जिम्मेदारी है. डर और प्रोफेशनल चिंता के लिए चुप रहना बिल्कुल गलत है इसे अस्वीकार किया जाएगा, जबकि गाजा में पत्रकारों को उनके काम के लिए हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है और कितने पत्रकारों को मार दिया जा रहा है. न्यूयॉर्क स्थित पत्रकारों की सुरक्षा समिति के मुताबिक, इजराइल और हमास के बीत ७ अक्टूबर को जंग शुरू होने होने के बाद कम से कम ९७ पत्रकारों को मार दिया गया, जिसमें से ९२ फिलिस्तीनी पत्रकार थे और १६ लोग घायल हो गए थे. बॉयकॉट के ऐलान के साथ ही एंटी वॉर समूह कोट पिंक ने बताया कि उनका आह्वान डिनर को रोकने के लिए था. उनका कहना था कि इजराइली सेना ने फिलिस्तीनी पत्रकारों को निशाना बनाने और हत्या करने में बाइडेन सरकार की मिलीभगत थी.
एक युद्ध-विरोधी गठबंधन डिनर वाली जगह वाशिंगटन हिल्टन होटल से कुछ ही दूरी पर एक प्रदर्शन की योजना बनाई. सभी प्रदर्शनकारियों ने डिनर में आए प्रशासन के अधिकारियों, पत्रकारों और मशहूर हस्तियों के लिए 'शर्म करो' के नारे लगाते हुए उनका स्वागत किया.

ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस... इजरायल ने राफा पर हमले से पहले हमास को दिया समझौते का आखिरी मौका

तेल अवीव-
इजरायल ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसके पास बंधक समझौता करने का आखिरी मौका है। अगर हमास समझौते पर सहमत नहीं होता है तो फिर उसकी सेना राफा शहर पर हमला कर देगी। हमास फिलहाल युद्धविराम के नए इजरायली प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। राफा इस समय विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए अंतिम शरणस्थली बना हुआ है। सीजफायर के लिए इजरायल और मिस्र के अधिकारियों के बीच लंबे समय से चल रही वार्ता शुक्रवार को समाप्त हुई है।चैनल १२ की रिपोर्ट के अनुसार, एक शीर्ष इजरायली अधिकारी ने कहा है कि मिस्र हमास पर समझौते के लिए दबाव डालने को तैयार है लेकिन इजरायल की ओर से राफा में आगे बढ़ने के

इरादे गंभीर हैं। अधिकारी ने कहा कि इजरायल हमास द्वारा किसी भी देरी के लिए सहमत नहीं होगा। हमास नेता याह्या सिनवार बंधकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे एक सुरंग नेटवर्क में छिपे हुए हैं। सूत्र ने कहा कि इजरायली सेना के राफा में जाने से पहले हमास के लिए यह आखिरी मौका है। वह या तो डील को मानेंगे या फिर उनको राफा में हमला देखना होगा। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, हमास के वरिष्ठ अधिकारी खलील अलहया ने कहा कि उनका नेतृत्व इजरायल के प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है और जल्द ही अपना जवाब देगा। उन्होंने इजरायल की पेशकश के बारे में कोई विवरण नहीं दिया। इस महीने की शुरुआत में हुई बातचीत में छह सप्ताह का युद्धविराम और बंधकों की रिहाई के बदले इजरायली जेलों में बंद सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को मुक्त करने की डील थी।इजरायल में हर रोज होते विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर बंधकों के परिवारों द्वारा उन्हें घर वापस लाने का भारी दबाव है। युद्ध लंबा खिंचने की वजह से सीजफायर का अंतरराष्ट्रीय दबाव भी है।

हज २०२४ के लिए सऊदी अरब सरकार ने लिया अहम फैसला, फतवा काउंसिल ने जारी किया आदेश

रियादः
सऊदी अरब ने हज करने को लेकर नियमों में सख्ती की है। सऊदी अरब की फतवा परिषद ने हज के लिए परमिट अनिवार्य घोषित करते हुए नियमों का कड़ाई से पालन करने की बात कही है। सऊदी अरब के वरिष्ठ विद्वानों की परिषद की ओर से जारी फतवे के अनुसार, आधिकारिक परमिट के बिना हज करना प्रतिबंधित किया जाता है। ये हज यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास के तहत उठाया गया कदम है। ये फतवा परमिट प्राप्त करने की जरूरत पर जोर देने के साथ-साथ इस्लामी कानून के तहत हज के महत्व पर भी प्रकाश डालता है।खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, आंतरिक मंत्रालय, हज मंत्रालय, ग्रैंड मस्जिद और पैगंबर की मस्जिद के मामलों की देखभाल के लिए बने सामान्य प्राधिकरण के सहयोग से ये निर्णय लिया गया है। सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हज करने की योजना बना रहे लोगों द्वारा स्थापित नियमों और दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों और जोखिमों के बारे में चिंताओं को देखते हुए ये फैसला लिया है।रिपोर्ट के मुताबिक, परमिट जारी करने से हज यात्रा से जुड़े अनुष्ठान सरल हो जाते हैं, जिससे शरिया द्वारा अनिवार्य सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित होती है। यह व्यवस्था, सुरक्षा बनाए रखने और भीड़भाड़ और संभावित भगदड़ को रोकने के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ विद्वानों की परिषद के अनुसार, हज परमिट प्राप्त करना न केवल एक कानूनी दायित्व है बल्कि इस्लामी शिक्षाओं के अनुपालन के लिए भी अहम है। जो लोग इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे वे न केवल कानूनी परिणामों से बचेंगे बल्कि उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा।इस साल यानी, २०२४ में करीब २० लाख भारतीय तीर्थयात्रियों के हज के लिए सऊदी अरब जाने की उम्मीद है। इस साल हज के लिए भारत से एक लाख, ३९ हजार लोग सऊदी अरब जाएंगे। देशभर से लोगों ने हज के लिए आवेदन किया था। इनमें से लॉटरी सिस्टम के जरिए १,३९०५४ हाजियों का नाम हज यात्रा के लिए चुना गया। करीब ३५ हजार लोग निजी रूप से भी हज पर जाएंगे। भारत और सऊदी की सरकारों के बीच बीते साल द्विपक्षीय हज समझौता हुआ है। इसके तहत हज २०२४ के लिए भारत से कुल १,७५,०२५ हाजियों का कोटा हुआ है। इसमें भारतीय हज समिति के माध्यम से १,४०,०२० सीटें आरक्षित की गई हैं।

इस देश में बर्फ की कीमत रोटी और दूध से अधिक, एक टुकड़े के लिए मरने-मारने पर उतारू अवाम

बमाकोः
अफ्रीकी देश माली में बर्फ के एक टुकड़े की कीमत रोटी और दूध से कहीं महंगी है। हालात इतने खराब हैं कि बर्फ के लिए लोग एक दूसरे से मारपीट करने से भी बाज नहीं आ रहे। यह सब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और अघोषित बिजली कटौती के कारण हो रहा है। लोग राजधानी बमाको में लंबे समय तक बिजली कटौती के कारण फ्रिज के काम न करने के कारण भोजन को बचाए रखने और लू के दौरान ठंडा रखने के लिए बर्फ के टुकड़ों का सहारा ले रहे हैं। माली में इस समय अधिकतम तापमान ४८ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है।बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, लोगों का कहना है कि बर्फ के कारण उनकी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें सुरक्षित रह पा रही हैं। यह कुछ हद तक काम तो कर रहा है, लेकिन बर्फ की कीमतों में हो रहे इजाफे ने जीवन को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया है। कुछ जगहों पर एक छोटे बैग के लिए १०० फ्रैंक सीएफए (१३.६ रुपये) चुकाने पड़ रहे हैं। यहां तक कि कुछ जगहों पर तो यह ४० से ५० रुपये तक मिल रहा है। इससे बर्फ की कीमत रोटी से अधिक हो जा रही है। माली में ब्रेड या रोटी के एक टुकड़े की कीमत लगभग

२५० सीएफए (३४ रुपये) है।माली में भीषण गर्मी और बिजली कटौती महिलाओं के लिए और अधिक संकट पैदा कर रहा है। महिलाओं को अब हफ्ते में कुछ बार के बजाए हर दिन खाना बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। बिजली कटौती के कारण खाना खराब हो जाता है। ऐसे में उसे फेंकना पड़ता है। इसके बाद गर्मी और उमस के बीच फिर से खाना बनाना होता है। इससे रसोई का बजट तो बिगड़ ही रहा है, साथ में उनके सेहत पर भी गर्मी का बुरा असर पड़ रहा है। भीषण गर्मी के बावजूद महिलाएं खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। माली में समस्याएं करीब एक साल पहले शुरू हुई। माली की सरकारी बिजली कंपनी हाल के वर्षों में करोड़ों डॉलर का कर्ज जमा करने के बाद बढ़ती मांग को पूरा करने में विफल रही है। कई लोगों के पास बैक-अप जनरेटर नहीं हैं, क्योंकि इसके लिए मिलने वाला ईंधन काफी महंगा है। बिजली नहीं होने का मतलब रात में पंखे नहीं होना है, जिससे कई लोगों को बाहर सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और इसका असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। लोगों को गर्मी के कारण चक्कर और मितली जैसी समस्याएं होती हैं। इससे निपटने के लिए उन्हें अक्सर अपने ऊपर पानी डालना पड़ता है।मार्च के बाद से, माली के कुछ हिस्सों में तापमान ४८ण से ऊपर बढ़ गया है, जिससे १०० से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक असुरक्षित बुजुर्ग और बहुत युवा लोग हैं। बमाको में विश्वविद्यालय अस्पताल में काम करने वाले प्रोफ़ेसर याकूबा टोलोबा कहते हैं, 'हम एक दिन में लगभग १५ अस्पताल में भर्ती होते देख रहे थे।' उन्होंने बीबीसी को बताया, 'कई मरीज डिहाइड्रेशन का शिकार हैं। मुख्य लक्षण खांसी और ब्रोन्कियल की है। कुछ को श्वसन संबंधी परेशानी भी होती है।'एहतियात के तौर पर कुछ इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और मुस्लिम बहुल देश में लोगों को हाल ही में खत्म हुए रमजान के दौरान रोजा न रखने की सलाह दी गई थी। प्रोफेसर टोलोबा कहते हैं, 'हमें इन स्थितियों के लिए और अधिक योजना बनाने की ज़रूरत है, जो शायद वापस आएंगी। इस बार इसने हमें आश्चर्यचकित कर दिया।'ष्ठ

सऊदी-इजरायल में पर्दे के पीछे चल रही बातचीत? मोसाद का सीक्रेट प्लेन गुपचुप पहुंचा था रियाद

तेल अवीव-
इजरायल और सऊदी अरब के बीच क्या पर्दे के पीछे कोई बातचीत चल रही है और दोनों रिश्ते सामान्य करने की ओर बढ़ रहे हैं। ये कयास इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एक विमान के सऊदी में उतरने के बाद लगाया जा रहा है। इस निजी विमान का इस्तेमाल मोसाद के अधिकारी काफी समय तक करते रहे हैं। ये विमान रियाद और तेल अवीव के बीच सामान्यीकरण वार्ता फिर से शुरू होने की संभावना के बीच सऊदी की राजधानी में उतरा, जो इजरायल के बेन गुरियन हवाई अड्डे से रवाना हुआ था।
ईरान के न्यूज नेटवर्क प्रेस टीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले महीनों में इस विमान का इस्तेमाल मोसाद के अधिकारियों के साथ-साथ इजरायल की आंतरिक सुरक्षा सेवा शिन बेट के अफसर भी करते रहे हैं। इस बार विमान में शीर्ष इजरायली अधिकारियों के रियाद पहुंचने की बात कही गई है, जो दोनों देशों के बीच संबंधों के संभावित सामान्यीकरण पर बातचीत करेंगे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की ओर से इजरायल और सऊदी के संभावित मेल-मिलाप में मध्यस्थता की जा रही है।संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने २०२० में इजरायली शासन के साथ अमेरिका की मध्यस्थता में सामान्यीकरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी फिलिस्तीन ने निंदा करते हुए इसे फिलिस्तीनी लोगों की पीठ में छुरा घोंपना बताया था। हाल ही में अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन लंबे समय तक चलने वाले राजनयिक समझौते पर जोर दे रहा है। इस डील में रियाद राजनयिक मान्यता के बदले में फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव

डालेगा।इजरायल को मान्यता देने के बदले में सऊदी को अमेरिका के साथ अधिक औपचारिक सैन्य संबंध, नागरिक परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने में सहायता और फिलिस्तीन के लिए नए सिरे से प्रयास की पेशकश की जाएगी। इजरायल और सऊदी अरब के बीच संभावित सामान्यीकरण वार्ता को बीते साल अक्टूबर में झटका लगा था।

बिजेपी की ४०० की फिल्म हो चुकी है फ्लॉप', तेजस्वी यादव ने साधा निशाना

पटना-

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी की ४०० की फिल्म फ्लॉप हो चुकी है. रविवार को सुपौल लोकसभा क्षेत्र के छातापुर विधानसभा क्षेत्र के हाई स्कूल मैदान में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी एवं राज्यसभा सांसद मनोज झा ने चुनावी सभा को संबोधित किया. इस अवसर पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कि बीजेपी के लोग डिप्रेशन में हैं.उन्होंने कहा कि बीजेपी की ४०० की फिल्म फ्लॉप हो चुकी है. बीजेपी के लोग डिप्रेशन में हैं. पूरे देश ने अपना मूड बना लिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी. पीएम मोदी आएंगे और जाएंगे, लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा, वह आएंगे, झूठ बोलेंगे, जहरीली भाषा बोलेंगे और ५ साल बाद फिर नजर आएंगे.उन्होंने कहा कि बीजेपी डिप्रेशन में है. पहले दो चरण बहुत करीबी रहे हैं. खासकर बिहार में हम आजीविका, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे मुद्दों पर अभियान चला रहे हैं. उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की. इसलिए, हम अपने वास्तविक मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.उन्होंने कहा कि लोग अब मोदी और भाजपा के झूठ से तंग आ चुके हैं. लोगों ने उन्हें १० साल दिए, लेकिन जमीनी हकीकत देखें तो कोई काम नहीं हुआ. इसलिए, इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हैं और हावी रहे हैं. यहां तक कि बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में ऐसा कुछ खास नहीं रखा है, जिसमें विकास की बात हो.दो चरणों के चुनाव के दौरान कम मतदान प्रतिशत पर तेजस्वी यादव ने कहा कि देश की जनता मौजूदा सरकार से निराश है. दो चरणों के मतदान के बाद तो बीजेपी के लोग डिप्रेशन में आ गए हैं. वैसे लोगों को वोट देने के लिए बाहर आना चाहिए, जो भी लोग बाहर आकर वोट कर रहे हैं, वो मौजूदा सरकार को भगाने आ रहे हैं.उन्होंने कहा कि मैं हमारी संभावनाओं को लेकर बहुत सकारात्मक हूं. हमने योजना और रणनीति के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. मैं यहां तक कहूंगा कि हमने एनडीए को रक्षात्मक स्थिति में डाल दिया है. मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग और न्यायपालिका जैसे स्वतंत्र संवैधानिक निकाय हमारे लिए प्रतिस्पर्धा के लिए समान अवसर तैयार करेंगे. पूरे देश में लोग बदलाव चाह रहे हैं.

एनडीए बैकफुट पर है

तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए बैकफुट पर है. उन्होंने वरिष्ठ विपक्षी नेताओं के पीछे जाने के लिए हर संभव कोशिश की है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवार और झारखंड के हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया है. केंद्रीय एजेंसियों ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. यह बुहत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. लोकतंत्र और संविधान खतरे में हैं. लोकतंत्र और संविधान को बचाना होगा और बीजेपी को हराना होगा.

अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद देवेंद्र यादव हो सकते हैं दिल्ली कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, आज ऐलान संभव

नई दिल्ली-

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद राजधानी की सियासत गरमा गई है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने लवली का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है. अब खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी देवेंद्र यादव को दिल्ली कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना सकती है. देवेंद्र यादव फिलहाल पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं. इसके पहले वो उत्तराखंड के प्रभारी रह चुके हैं.देवेंद्र यादव की गिनती दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है. इनको एआईसीसी के कोषाध्यक्ष अजय माकन का समर्थन भी प्राप्त है. कहा जा रहा है कि दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित को भी इनके नाम पर ऐतराज नहीं है. आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान को करना है. बताया जा रहा है कि पार्टी सोमवार को दिल्ली कांग्रेस के वर्किंग अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है.बता दें कि दिल्ली में टिकट बंटवारे को लेकर नाराज बताए जा रहे अरविंदर सिंह

लवली ने रविवार सुबह दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भेज दिया था. इस्तीफा स्वीकार होने के बाद लवली मीडिया के सामने आए और अपनी बात रखी. लवली ने कहा कि मैंने इस्तीफा अपने लिए नहीं दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए दिया है.

लवली बोले- मेरी पीड़ा उसूलों को लेकर है

उन्होंने कहा कि यदि मेरा इस्तीफा स्वीकार हुआ है तो बावरिया जी का धन्यवाद. मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करने नहीं जा रहा हूं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्कर ने यह नहीं कहा कि मौजूदा केजरीवाल सरकार को हमने क्लीन चिट दिया है. मैंने अपने मन की पीड़ा दिल्ली के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पीड़ा को मैंने अपने अध्यक्ष को भेजा है. मेरी पीड़ा उसूलों को लेकर है.

लवली के घर के बाहर आसिफ मोहम्मद से धक्का-मुक्की

ओखला से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद लवली के घर पहुंचे थे,उन्होंने लवली और सुभाष चोपड़ा की बीजेपी से मिलीभगत के आरोप लगाए. जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनसे जमकर बदसलूकी की और धक्के मार कर सोसाइटी से बाहर निकाल दिया.

उनका कहना है कि वो भी आम आदमी पार्टी से गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जब अलाकामान ने फैसला ले लिए तो हम उसके साथ ही.आलाकमान को लवली, सुभाष चोपड़ा और राजकुमार चौहान के खिलाफ कारवाई करनी चाहिए. जिसके बाद लवली के घर में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जमकर आसिफ से बदसलूकी की,मारपीट की,और धक्के मारकर सोसाइटी से बाहर निकाल दिया.

(पृष्ठ १ पर से..)

जम्मू-कश्मीर: घोटालों के जांचकर्ता सीबीआई

पड़ने वाले स्पीड ब्रेकर पर अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते ये हादसा हुआ.एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शर्मा के सिर पर गंभीर चोटें आई थीं. सूत्रों के मुताबिक, एक राहगीर ने अधिकारी को घायल अवस्था में जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) पहुंचाया.एक रिपोर्ट में बताया गया कि दुर्घटना के समय अधिकारी बिना हेलमेट के रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल चला रहे थे. हालांकि, द वायर स्वतंत्र रूप से इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं कर सका है.इस बीच, शर्मा के परिवार को दुर्घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद वे अस्पताल पहुंचे. सूत्रों ने बताया कि शर्मा का निधन उस समय हुआ जब उन्हें उनके परिवार द्वारा विशेष उपचार के लिए पंजाब के एक अस्पताल में ले जाया जा रहा था.शर्मा का पोस्टमार्टम जीएमसी जम्मू में किया गया, जिसके बाद उनका शव उनके परिवार को सौंप दिया गया है.एक बयान में जम्मू-कश्मीर पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि २६ अप्रैल को लगभग ११.५७ बजे सीबीआई (जम्मू) में तैनात डिप्टी एसपी प्रशांत शर्मा को जम्मू के जीएमसी में भर्ती कराया गया था. इसके बाद उन्हें आगे के इलाज़ के लिए डीएमसी लुधियाना (पंजाब) रेफर किया गया, जहां जाते वक्त उनकी रास्ते में ही मौत हो गई. इसके बाद चिकित्सीय और कानूनी औपचारिकताओं के लिए शव को जीएमसी जम्मू भेज दिया गया.बता दें कि शर्मा जम्मू-कश्मीर में उन कई घोटालों की जांच का नेतृत्व कर रहे थे, जो २०१९ में अनुच्छेद ३७० को हटाए जाने के बाद पिछले चार वर्षों में सामने आए थे.इनमें जम्मू-कश्मीर प्रशासन में उप-निरीक्षकों (एसआई) और जूनियर इंजीनियरों (जेई) की नियुक्ति में अनियमितताओं का मामला भी शामिल है, जिसकी चयन सूची को बाद में रद्द कर दिया गया था.पीडीपी के वरिष्ठ नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री नईम अख्तर ने इस घटना की जांच की मांग की है.नईम अख्तर ने कहा, 'इस तथ्य को देखते हुए कि दिवंगत डिप्टी एसपी (उपाधीक्षक) बहुत महत्वपूर्ण मामलों की जांच कर रहे थे, पीडीपी निष्पक्ष, समयबद्ध और विश्वसनीय जांच की मांग करती है. ताकि इस परिस्थिति को लेकर किसी संदेह की गुंजाइश न रहे. हम मृत अधिकारी के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं.'इस घटना के संबंध में जम्मू के पत्रकार तरुण उपाध्याय ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कहा है कि शर्मा जम्मू-कश्मीर पुलिस में उप-निरीक्षकों की भर्ती से जुड़े पेपर लीक घोटाले सहित महत्वपूर्ण मामलों की जांच कर रहे थे. वह आईएएस अधिकारी नवीन चौधरी के खिलाफ दर्ज मामले की भी जांच कर रहे थे.नवीन चौधरी पर जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किरू जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए ४,२८७ करोड़ रुपये का ठेका देने में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने मामला दर्ज किया था. इस मामले में एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से भी पूछताछ की थी.गौरतलब है कि शर्मा उस सीबीआई टीम का भी हिस्सा थे, जिसने जम्मू-कश्मीर की झेलम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और झेलम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जम्मू में बैंक ऑफ इंडिया की सतवारी शाखा से लिए गए ७३ करोड़ रुपये के ऋण के दुरुपयोग की जांच की थी.केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटालों की जांच भी सीबीआई को सौंपी थी.

फैक्ट-चेक: प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी भाषणों में लगातार झूठे दावे कर रहे हैं

देश में भूमि स्वामित्व में ऐतिहासिक असमानता का समाधान करने के लिए पेश किया गया था.

अप्रैल २३, टोंक-सवाई माधोपुर

दावा: राहुल गांधी के भाषण से एक्स-रे वाला संदर्भ उठाते हुए मोदी ने कहा, 'आपके घर में अगर बाजरे के डिब्बे के अंदर भी कुछ रखा है, तो वो भी एक्स-रे करके खोजा जाएगा. आपके पास अगर जरूरत से ज्यादा संपत्ति होगी तो उस पर कब्जा करके लोगों में बांट देंगे. अगर आपके पास दो घर हैं, तो एक्स-रे करके एक सरकार ले लेगी.'

तथ्य: न तो कांग्रेस के घोषणापत्र में और न ही उसके नेताओं के भाषणों में सरकार द्वारा लोगों के घरों को जब्त करने और बांटने का कोई उल्लेख है.

दावा: इसी भाषण में, मोदी ने वापस पहले वाला झूठा दावा दोहराया कि 'मनमोहन जी ने कहा था कि मुसलमानों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है'.

तथ्य: मनमोहन सिंह का उक्त भाषण प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा रखे गए संग्रह में उपलब्ध है. उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा एक स्पष्टीकरण भी जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 'प्रधानमंत्री का 'संसाधनों पर पहला अधिकार' का संदर्भ एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के उत्थान से था'.सिंह ने अपना भाषण हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के महीने भर बाद दिया था. रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में मुसलमान शिक्षा, आय और रोजगार के मामले में अन्य समुदायों से कितना पिछड़े हुए हैं.

अप्रैल २४, सागर

दावा: मोदी ने दावा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस ने गैरकानूनी तरीकों से धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की है. 'इसने सभी मुसलमानों को ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी आरक्षण का बड़ा हिस्सा छीन लिया और धर्म के आधार पर उन्हें दे दिया.'

तथ्य: १९६२ में, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि आर. नागणा गौड़ा आयोग की सिफारिश पर मुस्लिम समुदायों की कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल किया था. उससे बहुत पहले, मैसूर के महाराजा ने १९२१ में मुसलमानों के लिए आरक्षण की नीति शुरू की थी.बाद में, १९९४ में एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली जनता दल (सेक्युलर) सरकार ने कर्नाटक में सभी मुस्लिम समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल किया और उनके लिए ४इ उप-कोटा बनाया. जनता दल (सेक्युलर) वर्तमान में भाजपा की सहयोगी है.कर्नाटक उन १४ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है जहां सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर मुस्लिम समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल किया गया है.गुजरात, जहां मोदी १२ साल तक मुख्यमंत्री रहे, में भी मुस्लिम समुदाय ओबीसी में शामिल हैं. दो साल पहले एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में, मोदी ने राज्य में ७० मुस्लिम जातियों को आरक्षण का लाभ मिलने का दावा किया था.

अप्रैल २४, सरगुजा

दावा:मोदी ने कहा, 'कांग्रेस ने बरसों पहले आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया था और इसको पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई. उन्होंने धर्म के आधार पर १५ प्रतिशत आरक्षण की बात कही. ये भी कहा था कि एससी/एसटी/ओबीसी का जो कोटा है उसी में कटौती करके धर्म के आधार पर कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाए. २००९ के अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने यही इरादा जताया. २०१४ के घोषणापत्र में भी इन्होंने साफ-साफ कहा था कि वो इस मामले को कभी भी छोड़ेंगे नहीं.'

तथ्य: आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने २००५ में मुसलमानों को ५इ आरक्षण देने का कानून पारित किया था. हाईकोर्ट ने यह तर्क देते हुए कानून को असंवैधानिक करार दिया कि धर्म 'नागरिकों के किसी वर्ग को सामाजिक रूप से पिछड़ा निर्धारित करने का एकमात्र आधार' नहीं हो सकता. २००९ के अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने कहा कि वह अल्पसंख्यकों को 'उनके सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर' आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है. २०१४ के घोषणापत्र में कहा गया था, 'कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मौजूदा आरक्षण को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना सभी समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण शुरू करने के लिए एक रास्ता खोजने के लिए प्रतिबद्ध है.' पार्टी के २०१९ के घोषणापत्र में इस पर कुछ नहीं था, जबकि २०२४ के घोषणापत्र में कहा गया है, 'हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार, सार्वजनिक कार्य अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के अवसरों का उचित हिस्सा मिले.'

दावा: उसी भाषण में, मोदी ने यह दावा दोहराया कि कांग्रेस ने कर्नाटक में धर्म के आधार पर कोटा लागू किया था. उन्होंने कहा, 'जब वहां भाजपा सरकार आई तो हमने संविधान के विरुद्ध, बाबासाहेब आंबेडकर की भावना के विरुद्ध कांग्रेस ने जो निर्णय किया था, उसको उखाड़ फेंक दिया और दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को उनका अधिकार वापस दिया'.

तथ्य: मार्च २०२३ में कर्नाटक में भाजपा सरकार ने मुस्लिम ओबीसी के लिए ४इ उप-कोटा खत्म कर दिया था, लेकिन इसने दलितों और आदिवासियों को कोटा दोबारा आवंटित नहीं किया. बल्कि, इसने यह कोटा राज्य के प्रभुत्वशाली समुदायों, लिंगायत और वोक्कालिगाओं को हस्तांतरित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल २०२३ में इस आदेश पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि यह 'प्रथम दृष्टया गलत' है.

दावा: मोदी ने एक और दावा किया, 'अब कांग्रेस का कहना है कि वो विरासत कर (ष्हर्पेंूहम ऊँ) लगाएगी, माता-पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी. आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा.'

तथ्य: कांग्रेस के घोषणापत्र में इसका कोई उल्लेख नहीं है. इसमें बस इतना कहा गया है, 'हम नीतियों में उपयुक्त बदलावों के माध्यम से धन और आय की बढ़ती असमानता का समाधान करेंगे.' अमेरिका में रहने वाले कांग्रेस के पूर्व सलाहकार सैम पित्रोदा ने कहा कि विरासत कर एक 'दिलचस्प विचार' है, लेकिन पार्टी ने औपचारिक रूप से उनकी टिप्पणियों से खुद को दूर कर लिया है.

अपैल २४, बैतूल

दावा:मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी समूहों से आरक्षण छीनकर उन्हें 'खासम खास' या विशेष वोट बैंक को देना चाहती है. मुसलमानों को आरक्षण देने संबंधी दावे को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस 'अपने वोट बैंक को मजबूत करने' के लिए निजी संपत्ति को जब्त करके बांटने की साजिश रच रही है.

तथ्य: कांग्रेस का घोषणापत्र न तो धर्म आधारित आरक्षण की बात करता है और न ही संपत्ति के पुनर्वितरण की.

दावा: फिर से विरासत कर का मुद्दा छेड़ते हुए मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस झूठ बोल रही है कि यह केवल सैम पित्रोदा की 'व्यक्तिगत राय' है. सच्चाई ये है कि साल २०११ में भी कांग्रेस ने इस टैक्स की वकालत की थी.

तथ्य: २०११ में तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने विरासत कर का विचार रखा था. लेकिन इस पर विचार करने वाली कांग्रेस अकेली नहीं है. २०१७ में मोदी सरकार में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी यह विचार रखा था.

अप्रैल २५, आगरा

दावा: मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस की धर्म के आधार पर आरक्षण देने के लिए ओबीसी के २७इ कोटा का एक हिस्सा चुराने की योजना है. तथ्य: कांग्रेस के घोषणापत्र में धर्म आधारित आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है.

दावा: मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस की योजना परिवार के लोगों को मिलने से पहले ५५इसंपत्ति जब्त करने की है, फिर तर्क दिया कि 'जो संपत्ति आप अपनी अगली पीढ़ी को विरासत में दे रहे हैं, उसमें से आधे से ज्यादा ये टैक्स लगाकर लूटना चाहते हैं'

तथ्य: कांग्रेस के घोषणापत्र में इसका कोई संदर्भ नहीं है. सैम पित्रोदा की टिप्पणी से भी उसने खुद को अलग कर लिया है.

अप्रैल २५, मुरैना

दावा: मोदी ने दावा किया, 'जब इंदिरा गांधी नहीं रहीं और उनके बेटे राजीव गांधी को विरासत में उनकी संपत्ति मिलनी थी तो यह पैसा सरकार के पास न चला जाए, इसलिए अपनी संपत्ति को बचाने के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विरासत कर को खत्म कर दिया था.'

तथ्य: १९८५ में तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने जो खत्म किया था, वह मृत व्यक्ति की संपत्ति पर लगाया जाने वाला संपत्ति शुल्क था, न कि विरासत कर.

अप्रैल २५, आंवला

दावा: इस बार मोदी ने दावा किया, 'सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि कांग्रेस का इरादा संस्थाओं और दफ्तरों का भी सर्वे कराने का है. यानी अगर किसी पिछड़े दलित परिवार में दो लोग नौकरी में है तो एक नौकरी छीनकर यह लोग उनको देंगे, जिनका कांग्रेस के मुताबिक देश के संसाधनों पर पहला हक है.'

तथ्य: कांग्रेस ने न तो अपने घोषणापत्र में और न ही उसके नेताओं ने भाषणों में पिछड़े वर्ग या दलित परिवारों से नौकरियां छीनने की बात कही है. पार्टी के घोषणापत्र में कहा गया है, 'कांग्रेस जातियों और उप-जातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना करेगी. आंकड़ों के आधार पर हम सकारात्मक कार्रवाई के एजेंडे को मजबूत करेंगे.'

राजस्थान: मोदी की आलोचना पर भाजपा अल्पसंख्यक

नियमित प्रक्रिया थी, हम केवल उनका हालचाल जानने के लिए गए थे.'एसएचओ ने आगे कहा, 'आज (शनिवार) गनी मुक्ता प्रसाद नगर थाने पहुंचे और सवाल करने लगे कि पुलिस की गाड़ी उनके घर क्यों गई थी. जब हमने उन्हें समझाया कि यह एक नियमित प्रक्रिया थी, तो गनी ने पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और टकराव पर उतर आए. हमें उन्हें सीआरपीसी की धारा १५१ के तहत हिरासत में लेना पड़ा क्योंकि डर था कि गनी किसी अपराध को अंजाम दे सकते हैं. हमने उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया है.'गौरतलब है कि न्यूज़ २४ से बात करते हुए गनी ने कहा था कि वह बांसवाड़ा में की गईं प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणियों से निराश हैं और भाजपा के मुस्लिम सदस्य के तौर पर जब वह वोट मांगने जाते हैं तो मुस्लिम समुदाय उनसे सवाल पूछता है. बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के इन चुनावी बयानों की विपक्ष ने भी व्यापक आलोचना की थी.इस संबंध में, भाजपा के बीकानेर शहर जिलाध्यक्ष विजय आचार्य ने पुष्टि की थी कि गनी को उनके बयानों के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था.

महादेव सट्टेबाजी ऐप: गिरफ्तार एक्टर साहिल

एप से जुड़े थे जो कि महादेव सट्टेबाजी ऐप नेटवर्क का ही हिस्सा है. इस मामले में मुंबई पुलिस ने साहिल से पूछताछ भी की थी. मुंबई के माटुंगा पुलिस मेहादेव बेटिंग ऐप केस की जांच में साहिल खान का नाम सामने आया था. साहिल ने जमानत के लिए कोर्ट का रुख किया था लेकिन कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. उधर मुंबई लाए जाने पर पत्रकारों से साहिल ने कहा कि उन्हें देश की कानून व्यवस्था पर पूरा यकीन है.बताया जा रहा है कि कोर्ट से अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी से राहत नहीं मिलने पर एक्टर साहिल खान फरार हो गया था. उसने मुंबई छोड़ दिया था. जिसके बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी. इस दौरान पुलिस से बचने के लिए साहिल ने अपनी लोकेशन भी कई बार बदली. इससे पहले १५००० करोड़ रुपये के महादेव बुक बेटिंग मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने साहिल खान से पूछताछ की थी. ये पूछताछ करीब ४ घंटे तक चली थी. इस दौरान साहिल ने इस मामले किसी भी तरह की अपनी भूमिका होने से इनकार किया. उन्होंने साफ कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है.यह मामला पहले माटुंगा पुलिस ने दर्ज किया, जिसके बाद इसकी जांच के लिए इसे क्राइम ब्रांच की साइबर सेल को ट्रांसफ़र किया गया और फिर एघ्ऊ का गठन किया गया. प्रवर्तन निदेशालय महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले की जांच कर रहा है. वहीं मुंबई पुलिस ने ३२ लोगों के खिलाफ एक अलग मामला दर्ज किया है.बताया जा रहा है कि इस FIR ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई मुस्तकीम, सौरभ चंद्राकर, रवि उपल, शुभम सोनी जैसे कई लोगों के नाम हैं।

हम २ प्रधानमंत्री बनाएं या ४ हमारी मर्जी, तानाशाही

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि इंडी गठबंधन में चर्चा चल रही है कि इंडी अलायंस वाले वन ईयर वन पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी एक साल एक पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, पांचवें साल पांचवां पीएम. ये पीएम की कुर्सी का भी ऑक्शन करने में लगे हैं.आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है. महाराष्ट्र में ४८ लोकसभा सीटें है. राज्य में पांच चरणों में मतदान होने जा रहा है. वहीं चरणों का मतदान पूरा हो चुका है. बीते २६ अप्रैल को महाराष्ट्र की आठ सीटों पर मतदान हुआ था. ७ और २० मई के बीच तीन और चरणों में मतदान होगा.

बिजेपी पर क्यों नहीं होती कार्रवाई? आप का कैंपेन सॉन्ग बदलने के

तो वह गलत है. इससे पता चलता है कि लोकतंत्र खतरे में है. मैं चुनाव आयोग से BJP के किए गए चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई करने की अपील करती हूं.'चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स, १९९४ और ँ की गाइडलाइन्स का हवाला देते हुए कैंपेन सॉन्ग बदलने को कहा है. EC ने कहा कि AAP कैंपेन सॉन्ग में जरूरी बदलाव करके उसे दोबारा सब्मिट करे. सॉन्ग को चेक करने के बाद ही उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा. ँ ने ये भी कहा कि 'जेल के जवाब में वोट' वाली लाइन कई बार दोहराई गई है. ये केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स, १९९४ के तहत प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजिंग कोड की ँ गाइडलाइन और रूल (१() का उल्लंघन करता है.आतिशी कहती हैं, 'कैंपेन सॉन्ग में कहीं भी ँ का जिक्र नहीं है. यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करता है. इसमें तथ्यात्मक वीडियो और घटनाएं शामिल हैं.' उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने ँ के किए गए आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई नहीं की है.बता दें कि आम आदमी पार्टी के २ मिनट के कैंपेन सॉन्ग को पार्टी विधायक दिलीप पांडे ने लिखा और गाया है. यह गाना गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में जारी किया गया था. AAP लोकसभा चुनाव में सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया के बिना प्रचार कर रही है. दोनों नेता दिल्ली के शराब नीति केस में फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं.

मुंबई पुलिस ने बच्चों को बेचने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़

बच्चों में ११ लड़के और तीन लड़कियां हैं. बेचे गए शिशुओं की उम्र न्यूनतम ५ दिन से लेकर अधिकतम ९ महीने तक है. पुलिस उपायुक्त रागसुधा आर. पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एक ँ ष्एए डॉक्टर को भी हथकड़ी लगाई गई है. फर्टिलिटी पुलिस ने बताया कि यह रैकेट फर्टिलिटी सेंटरों में काम करने वाली महिलाओं की मदद से चलाया जा रहा है. छोटे बच्चों को बेचने वाले गिरोह के ७ लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

अमेठी के लिए राहुल तैयार नहीं, प्रियंका भी

भी हो जाएगा.बताया जा रहा है कि खुद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं है. इसके पीछे राहुल का तर्क है कि दोनों सीट जीतने पर वो जिस भी सीट को छोड़ेंगे वहां पार्टी और खुद उनको लेकर गलत संदेश जाएगा. वहीं, प्रियंका गांधी का कहना है कि संसद में तीनों गांधी को होना ठीक नहीं है. कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल है. क्षेत्रीय दल कर रहे है तो वो कर लें.कांग्रेस ने फिलहाल अमेठी और रायबरेली से अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, लेकिन अब तक पार्टी देशभर में ३१७ प्रत्याशी घोषित कर चुकी है. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बार रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और वह राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुईं हैं. उन्होंने दो दशक तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया.राहुल गांधी २००४ से २०१९ तक अमेठी से लोकसभा सदस्य रहे. साल २०१९ के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि, राहुल गांधी को केरल की वायनाड सीट पर जीत मिली थी. जहां से वो संसद पहुंचे थे. राहुल गांधी इस बार भी वायनाड सीट से मैदान में हैं. शुक्रवार को वहां मतदान भी संपन्न हो गया.

एलसीबी पुलिस निरीक्षक को पुलिस महासंचालक सम्मान चिन्ह

दैनिक सुफ्फा/ अकोला-

जिला पुलिस विभाग में उत्कृष्ट फ्रिज में रख देना कर्तव्य का पालन करने वाले स्थानीय अपराध शाखा प्रमुख पुलिस निरीक्षक शंकर शेल्के को पुलिस महासंचालक सम्मान चिन्ह प्रदान करने की घोषणा की गई है.जिले में हत्या, डकैती, सेंधमारी जैसे जटिल कैसे को सुलझाने में उन्होंने सफलता हासिल की है. उनके इस काम करने के कारण उसे संज्ञान में लेते हुए पुलिस दल ने उन्हें पुलिस महासंचालक सम्मान चिन्ह प्रदान करने की घोषणा की है.सेल के सम टी अन्य १० पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारियों को भी इसी पुरस्कार से नवाजा जाएगा. जिला पुलिस दल के गौरव में इस सम्मान से बढ़ोतरी हो गई है. आगामी १ में को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर पुरस्कार का वितरण किया जाएगा. राज्य की पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला ने सन २०२३ के लिए पुलिस महासंचालक सम्मान चिन्ह पुरस्कार घोषित किए हैं.

दिनदहाड़े घर से सवा लाख की चोरी

अकोला-

गौरक्षण रोड इलाके के कीर्ति नगर इलाके में स्थित कमला नारायण बिल्डिंग के एक घर में चोरी की घटना सामने आई है. दोपहर में अज्ञात चोर ने घर से सवा लाख रुपए का माल पार कर दिया। चोर द्वारा खदान पुलिस को दी गई चुनौती के मद्देनजर पुलिस की जांच में संजना शिवशंकर खटोड़ (४९) कीर्ति नगर में कमला नारायण बिल्डिंग में अपने फ्लैट में दैनिक काम कर रही थीं। वे एक कमरे में सामान रख रही थी। जबकि परिवार के अन्य सदस्य रोजाना की तरह काम पर गए हुए थे। इसी मौके का फायदा उठाकर अज्ञात चोर दिनदहाड़े घर में घुस गया और दो तोला आभूषण ३० ग्राम और २५ हजार रुपये नकद कुल १ लाख २० हजार रुपये लूट लिये.किसी अनजान शख्स को घर में घुसता देख घबराई महिला जोर से चिल्लाई और चोर घर से भाग गया. इस घटना की जानकारी जैसे ही खदान पुलिस को मिली तो पुलिस पहुंच गई. साथ ही स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल जाधव, पुलिस उपनिरीक्षक आशीष शिंदे ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया. संजना खटोड़ की शिकायत के आधार पर खदान पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया गया है.

५० फीट गहरी खाई में गिरी बस, ४० यात्री थे सवार, कई की हालत गंभीर

बस इंदौर से अकोला आ रही थी

अकोला-

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है. शनिवार की सुबह यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर ५० फीट खाई में जा गिरी. हादसे में करीब १५ लोग घायल हुए हैं. जिनमे से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है जानकारी के मुताबिक़, हादसा शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जन्सोदी के पास हुआ है. यात्रियों से भरी बस इंदौर से अकोला आ रही थी. बस में लगभग ४० यात्री सवार थे. इसी बीच शनिवार तड़के जसोन्दी गाँव के पास बस अचानक ख़राब हो गयी. ड्राइवर और कंडक्टर उतरकर बस की खराबी ठीक करने लगे. बस रुकी होने के वजह से कुछ यात्री नीचे उतर आये. ड्राइवर ने जैसे बस चालू किया बस अनियंत्रित होकर ५० फीट गहरी खाई में जाकर गिर गई.

लोगों की चीख - पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस - प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से

रेस्क्यू किया गया. हादसे में करीब १५ लोग घायल हुए हैं. जिनमे से कुछ की हालत गंभीर है. सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल बुरहानपुर भेजा गया. बताया जा रहा है बस चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है. यात्रियों का कहना है बस चालक शराब के नशे में था. फ़िलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है.

सड़कों पर रहता है आवारा मवेशियों का कब्जा

अकोला-

महानगर की जनता और सड़क पर चलने वाले राहगीर लंबे समय से आवारा मवेशियों की धमाचौकड़ी से परेशान हैं। यहां लगभग हर सड़क पर आवारा मवेशियों का आतंक है। मुख्य मार्ग से लेकर बस स्टैंड, सब्जी मंडी, तिलक मार्ग परिसर, गांधी चौक, जयहिंद चौक आदी परिसरों मे इन आवारा मवेशियों का जमावड़ा सर्वाधिक देखने को मिलता है। सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं से आए दिन दुर्घटना होने से लोग परेशान हैं।ये मवेशी आए दिन आपस में भिड़ जाते हैं जिससे सड़क से निकलने वाले वाहन चालक भी घायल हो रहे हैं लेकिन स्थानीय प्रशासन का इस ओर बिलकुल भी

ध्यान नहीं है। वहीं महानगर पालिका द्वारा पशु वाहन लाया गया, परंतु महानगर को अभी तक पशुओं के आतंक से निजात नहीं दिला पा रही है। पहले भी कई बार महानगर पालिका द्वारा दिखावे की कार्रवाई की गई किंतू ठोस नही हो पाई है। इसके बावजूद कार्रवाई के पते नहीं। आमजन की मानें तो कई बार महानगर पालिका को शिकायत करने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

कार दुर्घटना में बालापुर के थानेदार मामूली रूप से घायल

अकोला-

पुलिस थाने के थानेदार अनिल जुमले २७ अप्रैल को एक निजी वाहन में बालापुर से अकोला की ओर जा रहे थे, तभी राष्ट्रीय मार्ग पर व्याला और रिधोरा के बीच वाहन अनियंत्रित हो गया। इसमें वह मामूली रूप से घायल हो गये. थानेदार जुमले ने पुलिस सुरक्षा में बालापुर से अकोला तक लोकसभा की सभी ईवीएम मशीन भेजने की जिम्मेदारी निभाई. फिर सुबह साढ़े आठ बजे बालापुर थाने से थानेदार जुमले और सोहेल खान की कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क से नीचे खेत में पलट गई। दोनों मामूली रूप से घायल हो गये. दोनों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है

विभिन्न प्रकार के आम की खुशबू से महके बाजार, अन्य राज्यों के आम शहर में, अभी तक नहीं आए हैं गांवरानी आम

माना-

ग्रीष्म काल में आम की आवाज शुरू हो जाती है. इन दिनों बाजार में विभिन्न राज्यों के और विभिन्न प्रजाति के आम बाजार में उपलब्ध है. अन्य फलों की तुलना में नागरिक आम खरीदने को प्राथमिकता दे रहे हैं.इन दोनों जैसे-जैसे धूप तेज होती जा रही है वैसे-वैसे आम खाने की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता चला जा रहा है. अकोला शहर में हैदराबाद का लालबाग आम १०० से १२० किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है. इसी तरह का हैदराबाद का बादाम आम ८० से १०० किलो के हिसाब से बचा जा रहा है इसी क्षेत्र का बैंगनपल्ली आम १०० से १२० रुपए किलो, गुजरात का केसर आम २०० से २४० रुपए

किलो के हिसाब से उपलब्ध कराया गया है.अभी तक ग्रामीण क्षेत्र से देसी आम की आवक शुरू नहीं हुई है इसी तरह देवगढ़ का हापुस आम ६०० से ७०० दर्जन के अनुसार मिल रहा है वही उत्तर प्रदेश का दशहरे आम १०० से १६० किलो के अनुसार मिल रहा है.भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए लोग बड़े प्रमाण में विभिन्न प्रजाति के आम अपनी सुविधा के अनुसार खरीद रहे हैं.

भोजन के साथ आम का रस स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है जिसके कारण अधिकांश नागरिक आम का रस निकालकर इसका सेवन कर रहे हैं वहीं कलमी आम भी काट कर खाने के लिए ले जाया जा रहा है.

वर्तमान समय में फल और सब्जी बाजार में जहां देखो वहां आम ही आम नजर आ रहे हैं. आम की आवक बड़े प्रमाण में हो रही है जिसके कारण नागरिक आम खरीदने को प्राथमिकता दे रहे हैं जबकि अन्य फल इन दिनों केवल देखने के लिए रह गए हैं.

थम नहीं रहा आवारा कुत्तों का आतंक, शहर के हर गली-मोहल्ले में लोग हो रहे शिकार

अकोला-

अब शहर का ऐसा कोई मोहल्ला या गली नहीं है, जहां आवारा कुत्ते न हो। शहर के सड़कों से लेकर छोटे से छोटे गली मोहल्ले में इनका आतंक चल रहा है। जो हर दिन हर मोहल्ले-गली में किसी न किसी को काटते जरुर है। लगातार इनका आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद भी जिम्मेदार नगर निगम इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से डाग बाइट के मामले बढ़ने के साथ ही इनकी संख्या में तेज गति से बढ़ते ही जा रही है। निगम के आकड़ों के मुताबिक ही शहरी क्षेत्र में लगभग साढ़े आठ हजार कुत्ते है,

इनकी संख्या से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि इन्हें पकड़ा नहीं गया और संख्या नियंत्रण के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया तो यह शहरवासियों के लिए एक बड़ी समस्या बनकर सामने आएगा, वैसे अभी भी यह डागबाइट करते हुए लोगों को परेशान ही करने का काम कर रहे है। शहर की गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों का झुंड देखा जा सकता है। कई चौक-चौराहें में कुत्तों का झुंड आक्रमक होता है जो बाइक सवार, पैदल राहगीर या चारपहिया वाहनों के पीछे दौड़ते हैं, इसकी वजह से कई बार दुर्घटना का शिकार भी होते हैं। यह हाल शहर व ग्रामीण अंचल दोनों जगहों में है। लगातार बढ़ रहे कुत्तों के हमले को लेकर लोगों का यह कहना है कि मांस मटन की दुकानें इसका बड़ा कारण है। इन दुकानों के संचालकों द्वारा दुकान से निकले अपशिष्ट को जहां तहां फेंक दिया जाता है। अपशिष्ट को लेकर कुत्तों में लड़ाईया होती रहती है और यह आक्रमक रवैया अपनाने लगते है और धीरे-धीरे इनका आक्रमक रवैया लोगों के खिलाफ में भी देखने को मिलता है और परिणाम स्वरूप डाग बाइट के मामले बढ़ते ही जा रहे है।

आलंदा परिसर में नेत्र रोगियों के लिए निःशुल्क नेत्र शल्य चिकित्सा

अकोला-

अकोला-सामजिक एवं वैद्यकीय सेवा मे सक्रिय स्थानीय आयकॉन हॉस्पिटल की ओरसे सर्जरी अभियान के तहत आलंदा गांव में भव्य निःशुल्क नेत्र रोग जांच शिविर संपन्न हुआ. इस शिविर में २०० मरीजों की निःशुल्क नेत्र जांच की गई तथा चयनित २० गरीब एवं जरूरतमंद नेत्र रोगियों की निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी लायंस क्लब ऑफ अकोला एलीट के सौजन्य से आइकॉन हॉस्पिटल में की गई. इसमें अस्पताल की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. पूजा खेतान ने सर्जरी की. आयकॉन हॉस्पिटल में हाल ही में सर्जरी करानेवाले नेत्र रोगियों का बिदाई कार्यक्रम संपन्न हुआ.इस अवसर पर २० सर्जरी किये मरीजों को बिदाई दी गयी, लायंस क्लब ऑफ अकोला एलीट की

अध्यक्ष श्रीमती शशि मुरारका, रमाकांत खेतान, कनुभाई, शोभा राठी, किरण अग्रवाल, डॉ. माहेश्वरी, डॉ. तारा माहेश्वरी, डॉ. कैलास मुरारका, हरीश खेतान, सुमित्रा खेतान, लतिका खेतान, उषा बाहेती, हरीश मुरारका एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे.

इस अवसर पर आयकॉन हॉस्पिटल के अध्यक्ष डॉ. के के अग्रवाल एवं प्रबंध निदेशक डॉ. संतोषकुमार सोमानी ने आयकॉन हॉस्पिटल के मानवीय, सामाजिक एवं चिकित्सा सेवा गतिविधियों की जानकारी देकर महिला-पुरुष मरीजों एवं नागरिकों से इस चिकित्सा सेवा गतिविधि से लाभान्वित होने की अपील की.

लायन क्लब एलीट की श्रीमती शशि मुरारका, रमाकांत खेतान ने अपने विचार व्यक्त कर क्लब के उपक्रम की जानकारी दी.इस समय क्लब के सदस्यों ने सहयोग करने का वादा किया. कार्यक्रम में सर्जरी करनेवाली डॉ पूजा खेतान, बधिरीकरण तज्ञ डॉ आकिब व ओटी सिस्टर सुलोचना भवाने का सत्कार किया गया.इस समय आयकॉन के संचालक डॉ कमलकिशोर लड्डा,डॉ रामधन शिंदे, वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी व लायन क्लब ईलाईट के पदाधिकारी व सदस्य, बडी संख्या मे उपस्थित थे.

भीषण गर्मी से अकोला की जनता बेहाल.... हीटवेव से बचने के लिए करें ये उपाय

अकोला-

अप्रैल का महीना आते ही देशभर में गर्मी का दौर शुरू हो गया है। माह के तीसरे हफ्ते में सूरज आग उबल रहा है। भीषण गर्मी के कारण देश के ११ राज्य लू की चपेट में आ चुके है। शुक्रवार को इन ११ राज्यों के १७ शहरों का तापमान दोपहर के समय ४३ डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया।

महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, आंध प्रदेश के रायलसीमा, तेंलगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तरी मध्य प्रदेश, गांगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में ४२ से ४४ डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के १९ शहरों का तापमान ४० डिग्री से अधिक बना हुआ है। राजधानी भोपाल में दोपहर का पारा ३९.५ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में भी पारा ऊपर चढ़ा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी प्रदेशों पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड और गुजरात के कुछ हिस्सों में हीटवेव की स्थिति अगले ३ से ४ दिनों के बीच जारी रहेगी। पश्चिमत्तोर के राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में भी अगले एक से दो दिन के अंदर तापमान ४० डिग्री का पार पहुंच जाएगा। २० और २१ अप्रैल को गंगीय पश्चिम बंगाल में और ओडिशा में लू का दौर जारी रहने और उसके बाद धीरे-धीरे कम होने की

संभावना है।

अगले ५ दिनों के लिए लू की चेतावनी

२० और २१ अप्रैल को गंगीय पश्चिम बंगाल के कई/कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।२० अप्रैल को ओडिशा के कुछ हिस्सों में लू की चेतावनी रहेगी।२० से २४ अप्रैल को झारखंड, बिहार के अलग-अलग हिस्सों में लू की स्थिति रहेगी।२० अप्रैल को पूर्वी उत्तर प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु में भी लू का दौर जारी रहेगी।गंगीय पश्चिम बंगाल में भी गंभीर गर्मी की लहर की स्थिति होने की भी संभावना है।२०-२४ अप्रैल के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और केरल और माहे में गर्म और आर्द्र मौसम रहने की संभावना है।

लू से कैसे बचे?

लू से बचने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसे आप जरूर फॉलो करें।पूरे दिन नियमित रूप से पानी पीकर हाइड्रेटेड रहें।गर्मी से बचने के लिए सांस लेने योग्य, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें।बाहर निकलते समय धूप का चश्मा, छाता या टोपी और उसके उपयुक्त जूते पहनकर रखें।अधिक प्रोटीन वाले भोजन से दूर रहें और बासी भोजन का सेवन करने से बचें।शराब, चाय, कॉफी और सोडा जैसे पेय प्रदार्थों को पीने से बचें।